UJtged forcible parade of naked woeTncn in village Hosahalli, District Raichur, Karnataka

श्रीमती सुधा विजय जोशी (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान एक अत्यंत शर्मनाक और घिनौनी घटना की ओर आकर्षित करना चाहती हूं और एक महत्वपूर्ण मामला इस सदन से उठाना चाहती हूं।

कर्नाटक के रायचूर जिला में तुरा विहाल पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत होसाहल्ली गांव में 30 अगस्त को तीन महिलाओं को नंगा करके पूरे गांव में शाम के पांच बजे से लेकर साढ़े छह बजे तक घुमाया गया है। किसी नागप्पा नामक एक व्यक्ति की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से यह घृणास्पद हत्याकाण्ड हुआ। यह एक प्रकार की हत्या ही मैं कहती हूं क्योंकि स्त्री का जो मन है, उसकी इसमें हत्या की गई है। चार महिलाओं को बदले की भावना से गांव में नंगा घुमाने का इरादा था, लेकिन एक महिला उससे बच करके निकल गई और तीन महिलाएं इस अत्याचार का शिकार हो गईं। जिन्होंने यह अत्याचार किया उनमें से —इन तीनों में से एक महिला के पिता और भाई लगते हैं। ऐसा पिता समस्त पिता के रिश्ते पर लांछन है और ऐसा भाई जो बहिन की इज्जत बचाने की बजाए उसकी इज्जत पूरे गांव में उछालता है, यह भाई राखी का बंधन तो छोड़िये मानवता का बंधन भी वह नहीं मान रहा है। तो वह मनुष्य कहलाने के लिए भी लायक नहीं है। इस पाप और गुनाह के लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए पुलिस ने उनमें से किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तो पुलिस के इस निकम्मेपन का क्या कारण है? पुलिस से एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए और अगर पुलिस दोषी ठहरे, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, वह न हों, इसके लिए ढेर सारे कानून हमारी सरकार ने बनाये हैं, फिर भी यह अत्याचार होते ही रहते हैं और फिर भी हमारे सुसंस्कृत देश में इतनी भयानक घटना हो सकती है। इस पर हम सब को बड़ी ही गहराई से विचार करना चाहिए और इस घटना की पूरी जांच तुरंत की जाए, इसकी मैं आपके माध्यम से मांग कर रही हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRJ JAGESH DESAl):We are adjourning the House at 3.45 today because of the exhibition on Sarvepalli Redhakrishnan.

Shri Bhajan Lai to make a state-meat.

STATEMENT BY MINISTER Regarding Procurement/Minimum Support prices of Rabi Crops of 1988-89

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : महोदय, सरकार ने वर्ष 1989-90 के मौसम में बेची जाने वाली 1988-89 की रबी फसलों की वसूली के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं।

अच्छी औसत किस्म के गेहूं का वसूली मूल्य 1988-89 विपणन मौसम के दौरान 173 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 1989-90 विपणन मौसम के लिए 183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जोकि चालू वर्ष से 10 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होगा।

[श्री भजन लाल]

इसी तरह से अच्छी किस्म के जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है और 1989-90 विपणन मौसम के लिए यह मूल्य 135 रुपये से बढ़ा कर 145 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

चने की अच्छी औसत किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1989-90 विपणन मौसम के लिए 290 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 325 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जोकि 1988-89 विपणन मौसम के लिए निर्धारित मूल्यों से 35 रुपये अधिक है।

अच्छी औसत किस्म की सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1988-89 विपणन मौसम के दौरान 430 रुपए से बढ़ाकर 1989-90 विपणन मौसम के लिए 460 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो कि 30 रुपए अधिक है। वर्ष 1989-90 मौसम के लिए कुसुम यानी सनफ्लोवर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 440 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो 1988-89 मौसम में निर्धारित मूल्य से 25/- रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य तोरिया/सरसों के साथ इसके सामान्य बाजार मूल्य से अंतर के आधार पर अलग से घोषित किया जाएगा।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, दस रुपया क्विंटल गेहूं का, जौ का और चने का यह मूल्य बढ़ाया गया है और सरसों का मूल्य भी कुछ बढ़ाया गया है। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि लागत मूल्य आयोग अपने के बाद आप हमें यह बताएंगे कि यह जो आपने बढ़ाया है 10 रुपया प्रति क्विंटल, यह आज का जो लागत मूल्य है, उसके अनुरूप है या नहीं? मैं यह मानता हूं। कि यह जो बढ़ोत्तरी है, वह उसको लागत मूल्य, मेहनत के मुताबिक बहुत ही कम है। अतः मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किसान को, उसकी लागत मूल्य के मुताबिक उसकी फसल का मूल्य देने के लिए इन मूल्यों को और बढ़ाने का आपका इरादा है या नहीं है? और अगर है तो कितना-कितना? मैं इतना ही जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

SHRI VITtf ALRAO MADHAV-RAO JADHAV (Maharashtra): Sir, firstly I would like to welcome the increase in theprices]which has been announced by the hem. Minister of Agriculture. I am aware of the fact that last year he had raised the price of wheatTromRs.163 toRs.173 and now he has raised it to Rs. 183 p;r quintal, which means in one year *hi* his raised the price by Rs. 20 per quintal. This is a very welcome step which the hon. Minister has taken. For birley, the price has teen in. creased by Rs. 10 and the minimum support price for gram of fair average quality has been fixed at Rs. 325, which is Rs. 35 more than that *of* 1938-89. In the case of safflower it is Rs. 25 more and for mustard it is Rs. 30 more. It is a welcome step, but there are a few doubts in my mind. Whatever prices are fixed by Government of India, areth^ same being given to the farmers? That is a very important aspect. Whenever there is a bumper harvest, the exploi-

tation is also hamper *m* the matkst.

Why I would like to raise this issue is because this year we are having an unprecedented monsoon. We are hiving bitter rainfall throughout the country. *{Interruption)* There should be a break also. From the agricultural point of view, if there is continuous rainfall for three months, you will not find a single crop on the land. So there should be a break also. Winn we look to the monsoon this year, it has rained so much and if it properly utilised, we can harvest the maximum yield which we could not do since Independence. Now when the bump;r yield is there, if there is no marketing arrangemeni. again some of the traders will go into the market and purchase the farmers produce at a veryflow price. But they will sell it at the same price to others or to the Government and thereby exploit the profit. So what is your po.ition regarding abolishing the middlemen from the market. Unless you abolish the middlemen from the market, the farmers will not get social and economic justice.

Second point is. may I ask the hon. Minister if these prices are fixed as *p-;r* the recommendations of Agricultural Cous and Prices Commission of so, whit arc their recommendation and on what basis have they made those recommendations? What is th; co>t of cultivation for each of the crops.

Secondly.. ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESA1): No, thirdly and lastly, because we want the Minister to reply also.

SHRl VITHALRAO MADRAS RAO JADHAV. That is all right, but it is a very important issue.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHR1 JAGESH DESAI): 1 do not mind it, hut because we have to adjourn the House at 3.45 and we want the reply of the Minister also.............

SHRl VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV: I know that, Sir, but there is no major opposition parly also there.. . .only Mr. Matto is there.

May I ask the Minister whether we have a policy decision that the profession of agriculture should be declared as an industry?

Now. there are different agro-climatic zones and different crops are grown in the different agro-climatic zones. So. what are your criteria for calculation of the prices of the different crops, based upon the different agro-climatic zones?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Jadhav, you have to allow others also to speak.

SHRl VITHALRAO MADHAV-RAO JADHAV:l would like to tell the honourable Minister that when the agricultural production is more, unless you create more industries, unless you create more food processing plants, unless you create agro-based food industries, the total harvest or total production which comes into the market cannot be consumed. So, what is your arrangement for that and what is your programme to create new agio and food processing plants under the separate

[Shri Vithatrao Madhavrao Jadhav]

Ministry which has been formulated by the Government of India? Thank you. Sir.

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मीर) : वाइस चेयर मैन, सर, मैं उर्दू में पूछूंगा । मैं जनावे मंत्री महोदय की तवज्जोह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने यह दस रुपए बढ़ाए हैं व्हीट के। तो मुझे जो इल्म है, वह मैं जानना चाहता हूं उसे, जो हरियाणा की मंडियों में और पंजाब की मंडियों में इस वक्त जो जिन्स है, वह किस भाव में आम लोग, जो आम मिल वाले दूसरे प्राइवेट व्यापारी हैं, किस भाव में खरीदते हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी जो पिछले साल बहुत जबरदस्त आफातें समावी आई थी, हमने उसका मुकाबला किया तो उसकी एक वजह थी, वह वजह थी कि हमारे पास काफी बम्पर स्टाक था। जो स्टाक हमने जमा किया, वह स्टाक जमा करने के लिए हमको उतना ही देना होगा उन जमींदारों को, जितने कि वह प्राइवेट वाले देते हैं। हरियाणा की मंडियों के मुतालिक उनको पूरा इल्म होगा, पंजाब की मंडियों के मुतालिक मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो हम देते हैं कीमत जमींदारों को, उससे बीस-बीस रुपए ज्यादा वे देते हैं, जो कि मिल वाले दूसरे हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए, अगर वह देते हैं तो हमारी जो लाईन है, सप्लाई लाईन, वह खराब हो जाएगी। उसका ख्याल रखना होगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think this is minimum support price.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: The question is not of minimum support price. I am talking of the Public Distribution pipeline. Unless this distribution pipeline is replenished, because we have saved the situation as a result of the drought last year only when we had enough stocks, and when you are not able to get it at the rates fixed, we can not replenish it

उसके मुताबिक मैं पूछ रहा हूं ।

दूसरी बात, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन्होंने फेयर प्राइस मस्टर्ड की 460/- रुपए कर दी। तीन दिन हुए, श्री जसवंत सिंह जी ने एक स्पेशल मेंशन किया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि राजस्थान में बहुत मुसीबत पड़ी है वहां के लोगों को, वहां जो भाव मस्टर्ड सीड, आयल जो मस्टर्ड का है, वह बहुत कम हो रहा है और उसके खरीदार मिलते नहीं हैं, कीमतें कम हो गई हैं। तो इसके मुतालिक उनकी क्या मालूमात है। यह मैं जानना चाहता हूं ताकि इसका इल्म हो जाय। अब जैसा जाधव जी ने कहा कि इस साल मानसून अच्छा होने से गुजरात और राजस्थान में उम्मीद है कि मस्टर्ड और दूसरी चीजें मिलेंगी। तो उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया है उसे बाजार में ले जाने के लिए?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह यहां रबी क्रोप की बात है।

श्री गुलाम रसूल मट्टू : नहीं-नहीं, खरीफ की भी बात है। तो मैं इन्ही पाइंटस पर जवाब चाहता हूं ।

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, इस वक्त बाजार में गेहूं 250/- रुपए और 275/- रुपए क्विंटल बिक रहा है और सरसों का रेट 700/-

क्विंटल है। मैं मंत्री जी से, वह किसान नेता हैं, जानना चाहता हूं कि यह जो 10/- रुपए वृद्धि की है, इसका बेसिस क्या है ? पहले साल आपने 63/- रुपए, फिर 10/- रुपए बढ़ाए, अब की 10/- रुपए बढ़ा दिए, यह कौनसा अर्थमैटिक्स है, समझ में नहीं आया। किसानों की लागत का हिसाब लगाने वाले और भी संस्थान देश में हैं, उनके अनुसार कह रहा हूं, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है, कम से कम 190/- रुपए गेहूं की होना चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं ?

दूसरा सरसों का जो आपने मूल्य रखा है, श्रीमन्, इसके लिए मैं कहूंगा, इसको कम से कम 500/- रुपए कर दो क्योंकि बाजार में इस वक्त यह 700/- रुपए क्विंटल बिक रहा है। आप इसकी सपोर्ट प्राइस 500/- रुपए क्विंटल कर दीजिए। आप मेहरबानी कर के 500 रुपए सपोर्ट प्राइस कर दीजिए। ये दो छोटी-छोटी मेरी क्वेरीज हैं।

श्री भजन लाल : : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय विकल साहब ने इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगे हैं और दूसरी माननीय सदस्यों ने भी मांगे हैं। जाधव साहब और मट्टू साहब ने भी मांगे हैं।

महोदय, सभी सदस्य अच्छी तरह जानते हैं और किसान भी समझते हैं कि उनकी लागत क्या आती है और भाव किस तरह तय किए जाते हैं। इन्होंने कहा कि लागत कुछ ज्यादा आती है और भाव सरकार कुछ कम देती है। सरकार एक-एक बात को पूरी तरह से आंककर, देखकर किसान को अपना अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ताकि किसान को इससे नीचे भाव पर न बेचना पड़े। किसान बहुत मेहनत से अपनी जिन्सें पैदा करता है और जब तक ये न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किए गए थे उस वक्त तक किसान की क्या हालत थी यह आपको पता है। माल मंडियों में पड़ा सड़ता था, कोई लेनेवाला नहीं होता था। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार ने एक फैसला किया कि चूंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान को अच्छा भाव मिलना चाहिए। उसे अच्छा भाव देने के लिए एक नीति अपनायी गयी कि कम-से-कम यह भाव मिलना चाहिए, इस भाव से नीचे किसान का अनाज नहीं बिकना चाहिये जो उसका खर्चा कुछ लाभ का हिसाब लगाकर यह किया जाता है।

महोदय, जो कम-से-कम भाव तय किया जाता है वह सारी बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसमें मजदूर लेबर का भी हिसाब लगाते हैं, भाड़े पर लिए गए पशु या ट्रैक्टर्स का भी हिसाब लगाते हैं, भाड़े पर ली गयी मशीनें, बीजों का हिसाब, खरीदे हुए बीजों की कीमत, खाद की कीमत, रासायनिक उर्वरक, उपकरणों और फार्म भवनों का मूल्य ह्रास, सिंचाई प्रभाव, भू-राजस्व, चल पूंजी पर ब्याज, विविध खर्च, जमीन का पट्टा -- इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। ये सारा खर्च निकालकर मेरे अंदाज में किसान को दो हजार प्रति एकड़ का फायदा जरूर होना चाहिए। इसके हिसाब से भाव तय करते हैं। इसमें माननीय सदस्यों की हमेशा यह मांग रही है कि इसमें किसानों के नुमाइंदे होने चाहिए। इस बार प्रधान मंत्री जी ने बड़ा शानदार फैसला लिया कि कृषि आयोग, जोकि भाव निर्धारित करता है, उसके चैयरमैन भी किसान है। उसमें कुल

[श्री भजन लाल]

मिलाकर तीन किसान के बेटे मेम्बर हैं जो किसान के घर पैदा हुए हैं और एक-एक बात को देखकर भाव तय करते हैं। लेकिन भाव तय करते समय अगर अकेले किसान का ही ख्याल रखा जाय तो यह भी मुनासिब नहीं हैं। इसमें कर्मचारी, अधिकारी और गरीब आदमी भी हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जिन्हें अनाज मोल लेकर खाना होता है। उनका हिसाब भी सरकार को रखना पड़ता है ताकि उन पर भी ज्यादा भार न पड़े। जब ज्यादा भार पड़ता है तो वह किसान के हित में भी नहीं होता है। किसान बड़ी मुश्किल से 5-6 चीजें बेचता है और कम-से-कम सौ डेढ़ सौ चीजें किसान को मोल लेनी पड़ती हैं। खेती में काम आनेवाली चीजें और घर में इस्तेमाल होनेवाले चीजें—इन सबका भार किसान के ऊपर पड़ता है। इसलिए भारत सरकार सोच-समझकर भाव तय करती है ताकि किसान को भी लाभकारी मूल्य मिले और लेनेवालों को भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

महोदय, जाधव साहब ने कहा कि किसान का जो भाव आप तय करते हैं क्या उस में मंडियों में माल बिक जाएगा। अगर उससे नीचे एक रुपया भी जाएगा तो भारत सरकार बीच में आएगी एक-एक दाना पर्चेज करेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): उसके लिए आपकी व्यवस्था क्या है?

श्री भजन लाल: उसके लिए एफ. सी. आई. है, नैफेड है, स्टेट्स में फूड डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारे मिलकर जहां भी जो व्यवस्था हो सकती है, करते हैं ताकि किसान का माल ठीक भाव में बिक सके। इसके साथ-साथ मट्टू साहब ने कहा कि प्राइवेट वाले ज्यादा भाव में ले रहे हैं लेकिन वह तो बहुत थोड़ा सा है, वह लेते नहीं हैं। सपोर्ट प्राइस से भी ऊपर बिके, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा भाव पर बिके किसान का माल। किसान कहीं भी सारे देश में माल ले जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। कहीं उसको फालतू मिलता हो तो, फालतू दाम लेना चाहिए। जहां तक भाव का ताल्लुक है, सरसों का जिक्र किया। सरसों का भाव भी आप जानते हैं कि 460 रुपए हमने इस बार दिया है जो कि पहले कभी इतना भाव नहीं था। हर जिन्स का जो ज्यादा-ज्यादा बढ़ा सकते थे, वह बढ़ाकर किसान को भाव दिया है ताकि किसान लाभकारी मूल्य हासिल कर सके और देश की और भी अधिक सेवा कर सके, ज्यादा उत्पादन करके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन से यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा भाव इस दफा भारत सरकार ने तय किया है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI JAGESHDESAI):The House now stands adjourned and will meet again tomorrow, Tuesday, 6th September. 1988 at 11.00 A.M.

The House then adjourned at fiftyone minutes past three of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 6th September. 1988.

MGIPRRND-2463 RSS/88See VI--Day-28.12.88-400